has not resulted in any change in the equalised price of Rs. 117.50 nP. per ton f.o.r. destination at which the State Trading Corporation is selling cement to the consumers.

Import of Automobile Tyres

*1597. **Sardar Iqbal Singh:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) whether *ad hoc* licences to import automobile tyres were granted in the past two years;

(b) if so, the names of the parties to whom these licences were granted together with the value of each licence;

(c) whether the licences were fully utilised;

(d) whether it is a fact that the Tariff Commission had recommended the introduction of an element of competition in the import of tyres; and

(e) if so, the reasons for departing from the recommendations of the Tariff Commission?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix VI, annexure No. 79.]

(c) Information regarding the extent to which the licences were utilised is not available.

(d) Yes, Sir.

(e) As the prices of imported tyres were ruling high it was considered desirable to arrange for a common pooled price for both imported and indigenous tyres.

Land for Rehabilitation

*1599. **Shrimati Renu Chakravartty:** Will the Minister of **Rehabilitation and Minority Affairs** be pleased to state:

(a) whether requisition has been made to Ministry of Railways by the West Bengal Government to permit the 54 acres of vacant and waterlogged land owned by Eastern Railway in Mouza Ghola and Vamanpur under Panihati Municipality P.S. Khardah 24 Parganas to be used for refugee rehabilitation; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri P. S. Naskar): (a) and (b). The State Governmnet have informed that they made a reference to the Ministry of Railways about the transfer of certain land belonging to them (Railways) in Mouza Ghola, P.S. Khardah in August, 1958. A reply is still awaited.

फरीदाबाद का कस्बा

*१६०१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद के कस्बे में, जहां बहुत कम कारखाने हैं, रहने वाले बहुत से बेरोजगार विस्थापित परिवारों को काम दिलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ख) उनमें स्थानीय श्रमिक कितने हैं और बाहर के लोग कितने हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० गास्कर) : (क) फरीदाबाद में ४० से भी अधिक कारखाने स्थापित किये जा चुके हैं और इन में लगभग २६०० शरणार्थियों को रोजगार मिलता है । कुछ शरणार्थी निजी व्यापार और कामों और फरीदाबाद डिवल्पमेंट बोर्ड की मदों में रोजगार पाते हैं । किसी दूसरे कस्बे में पुनर्वास मंत्रालय ने इतनी बड़ी तादाद में कारखाने स्थापित नहीं किये हैं । सरकार सब शरणार्थियों को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती । सारे देश में रोजगार की हालत को देखते हुए स्थिति का अवलोकन करना है ।

(ख) इन कारखानों में २६०० शरणार्थी और २६०० गैर-शरणार्थी काम करते

हैं । गैर-सरकारियों में से १२०० व्यक्ति टैकनीकल और कलात्मक कामों में लगे हुए हैं ।

तिहाड़ बस्ती में विस्थापित व्यक्ति

*१६०२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की तिहाड़ बस्ती में जो अपने मकान बनाने के लिये ५०० रुपये विस्थापित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में दिये गये थे उसके बदले में दावों की रकम में से उन से १०४० रुपये वसूल किये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि बाद में वसूली की राशि बढ़ा दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और इस के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० छे० लास्कर) : (क) सरकारी जमीन पर छोटे टेनोमेंट बनाने के लिये शरणार्थियों को ५०० रुपये दिये गये थे । गैर-दावेदार शरणार्थियों को दी दी गयी यह रकम अनुदान समझी गयी थी और उन से केवल जमीन की कीमत वसूल की गयी थी । दावेदार शरणार्थियों के दावों में से इस ५०० रुपये की रकम के अतिरिक्त जमीन की कीमत भी वसूल की गयी थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) कालोनी में अधिक सुविधाओं पर खर्च के कारण १३५० रुपये ।

वस्त्र के निर्यात में कमी

*१६०३. **श्री अमरेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन को भारतीय वस्त्र का निर्यात घट रहा है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं, या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) इसके कारण हैं मांगों में कमी होना, प्रतियोगिता बढ़ जाना तथा लंकाशायर में बन सकने वाले स्थानीय माल का सम्भवतः अधिक उपयोग होना ।

(ग) निर्यात बढ़ाने के सामान्य उपाय करने और उत्पादन शुल्कों को युक्तियुक्त आधार पर लाने के अलावा स्थिति पर बराबर नजर रखी जा रही है और उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

Jungpura Bridge

*1604. **Shri Sarju Pandey**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether the special investigation officer has submitted his report regarding the causes of damage to the approach road to the Jungpura bridge (Delhi);

(b) if so, what are his findings; and

(c) what action has been taken thereon?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda): (a) Yes, Sir.

(b) His findings are that the damage was due to the cumulative effect of the following:

(i) The unprecedented heavy rain on the 20th-21st of July 1958,

(ii) Improper and inadequate consolidation of earth work, particularly near the abutments of subways and bridges;